12.48 hrs.

BUSINESS OF THE HOUSE

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND SHIPPING AND TRANSPORT (SHRI RAGHU RAMAIAH) : With your permission, Sir, I rise to announce that Government Business in this House during the week commencing 4th May, 1970, will consist of :—

(1) Furuher consideration and passing of : The Finance Bill, 1970.
The Petroleum (Amendment) Bill, 1969.

(2) Consideration and passing of : The Contingency Fund of India (Amendment) Bill. 1969.
The Merchant Shipping (Amendment) Bill, 1969, as passed by Rajya Sabha.
The North Eastern Council Bill, 1969.

(3) Discussion on the Report of the Study Team on Prohibition on a motion to be moved by Shri Prakash Vir Shastri at 5 p.m. on Thursday, the 7th May, 1970.

श्री रवि राय (पुरी) : अध्यक्ष महोदय, मुझे निवेदन करना है कि अभी तक सरकार की तरफ से इस बारे में कोई ऐलान नहीं हुआ है कि देशी रियासतों के भूतपूर्व शासकों अर्थात् भूतपूर्व राजा, महाराजाओं के निजी कोष को खत्म करने के लिए सरकार इस सत्र में कब संविधान संशोधन विधेयक ला रही है ? आप जानते हैं कि इस सदन में बार बार प्रधान मंत्री और गृह मंत्री द्वारा आश्वासन दिया गया है कि वह इस सम्बन्ध में आवश्यक संविधान संशोधन विधेयक इसी बजट सैशन के दौरान लायेंगे। लेकिन अभी जो अगले सप्ताह के लिए कार्यक्रम पेश किया गया है उसमें इसका कोई भी जिक्र नहीं है इसलिये में सरकार से आप के माध्यम से स्पष्ट तौर पर जानना चाहूंगा कि वह इस के लिए जरूरी कांस्टीट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसी बजट सैशन के सत्र में लाने जा रहे है या नहीं ? मेरा आरोप है कि सरकार इस को लाना नहीं चाहती है क्योंकि इन के मंत्रीमंडल के एक सदस्य श्री भानु प्रकाश सिंह इस बारे में दूसरे लोगों को जोकि नहीं चाहते कि यह इस सैशन में पेश किया जाये उन्हें वे इकट्ठा कर रहे हैं।

मेरा दूसरा निवेदन है कि सी.एस.आई. आर. की रिपोर्ट के बारे में सदन के इसी सैशन के अन्दर बहस होनी चाहिए।

तीसरा निवेदन यह है कि शैडयूल्ड कास्ट्स एंड शैडयूल्ड ट्राइब्स कमिश्नर की लगातार तीन रिपोर्टें आ चुकी हैं लेकिन उन पर अभी तक बहस सदन में नहीं हो सकी है इसलिए उन पर भी बहस के लिए सैशन में समय निकाला जाये।

चौथा और आखिरी निवेदन यह है कि चौथी पंचवर्षीय योजना की जो ड्राफ्ट रिपोर्ट है उस पर भी इसी सैशन में बहस होनी चाहिए। यह चार हम लोगों की मांगें हैं।

श्री राम सेवक यादव (बारबंकी) : खाद्य और कृषि मंत्रालय की बजट डिमांड्स पर कल बहस हुई लेकिन चूंकि समय नहीं था इसलिये ज्यादा उन पर विचार नहीं किया जा सका। आज पूरे देश में खास तौर से उत्तर प्रदेश और बिहार में गन्ना सूख रहा है सरकार ने गन्ने के दाम निश्चित किये हैं 7 रुपये 37 पैसे प्रति क्विंटल लेकिन नोबत यह आई हुई है कि उससे 2 रुपये फी क्विंटल क्रशर खरीद रहे हैं और उन बेचारों की हालत बहुत ही खराब है। गुड़ के दाम भी बहुत गिर गये है, गन्ने के दाम मैं ने पहले ही बतलाया कि गिर गये हैं। किसान आज वहां बुरी तरह से तबाह हो रहे हैं और मैं चाहूंगा कि इसी सत्र में इस विषय पर विचार करने के लिए समय अवश्य निकाला जाये।

श्री रणधीर सिंह (रोहतक) : हम भी पूर्व वक्ता के कथन से सहमत हैं और चाहते हैं कि इस मसले पर इसी सैशन में बहस हो।

SHRI S. M. BANERJEE (Kanpur) : I am sure, Sir, you remember that the Home Minister gave a solemn promise to this House that the Bill on abolition of the

[Shri S. M. Banerjee]

Privy Purses will be introduced in the budget session. But, Sir, there is no time now.

I want to know from the hon. Minister whether the Government has any intention bring forward this Bill. If so when? My second point is this that in the other House, the hon. Prime Minister announced that she would include a labour representative in the Pay Commission. Unfortunately, nothing has been announced in this House.

I would request through you that she may announce that a labour representative would be included in the Pay Commission. My other point is this. I would request you to kindly ask the Prime Minister or the Minister of External Affairs to make a statement to-day on the naked invasion of the American imperialists on Combodia that has been made.

SHRI PILOO MODY (Godhra) : Also, we must have a discussion on the Chinese invasion of Combodia?

MR. SPEAKER : There is a Calling Attention Motion. That has been allowed on Monday.

श्री गुणानन्द ठाकुर (सहरसा): अध्यक्ष महोदय, मैं दो, तीन बातों की ओर प्रधान मंत्री जी का ध्यान आपके माध्यम से खींचना चाहता हूं। पहली बात यह है कि कल और आज में मुझे करीब तीन, चार तार इस आशय के मिले हैं कि उत्तर जिले के दरभंगा व सहरसा और पूर्णिया जिले में भयंकर आंधी चलने के फलस्वरूप सैकड़ों आदमी मर गये हैं। सहरसा जिले में अब तक 35 आदमी मरे हैं। मैं चाहूंगा कि प्रधान मंत्री फंड से उन लोगों को तत्काल सहायता मिले।

दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि बिहार विधान सभा और अब उत्तर प्रदेश विधान सभा द्वारा भी अपने यहां की विधान परिषदको खत्म करने का प्रस्ताव पास कर दिया गया है तो मैं प्रधान मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इस सैसन में वह इन दोनों राज्यों कि विधान परिषदों को समाप्त करने के बाबत आवश्यक लेजिस्लेशन लाने जा रही है अथवा नहीं। पंजाब और बंगाल का मामला सामने है।

जैसा मैंने अभी कहा सबसे बड़ी समस्या उत्तर बिहार के विकास की है। प्रधान मंत्री ने 175 करोड़ रुपया पिछड़े क्षेत्रों का विकास करने के लिए रक्खा है। मैं जानना चाहता हूं कि उत्तर बिहार में विकास कार्य सम्पन्न करने और पिछड़ापन दूर करने के लिए उस में से कितना रुपया दिया जायेगा? उत्तर बिहार की हालत बड़ी ही शोचनीय है। कोसी तट बांध के भीतर कोई डेढ़ लाख लोग शरणार्थियों का जीवन बिता रहे हैं। सहरसा जिले में कोई उद्योग नहीं है हालांकि जूट का बहुत बढ़िया उत्पादन वहां पर होता है। मैं जानना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री जी उत्तर बिहार में विकास कार्य करने के लिए उस अपने फंड में से कितना पैसा देना चाहती हैं?

श्री शिवचन्द्र झा (मधुबनी) : अध्यक्ष महोदय, यह नियम 193 के अन्तर्गत जो अगले सप्ताह विचार के लिए मोशंस एडमिट हो गये हैं उन सभी मोशंस पर विचार किया जायेगा अथवा नहीं? चूंकि मेरा भी मोशन उनमें से एक है इसलिए मैं यह जानना चाहता हूं।

श्री रामावतार शास्त्री (पटना) : मुझे दो बातें निवेदन करनी हैं। पहली बात तो यह है कि कल हालांकि हम लोगों ने हाउस में देश की अन्न स्थिति के बारे में चर्चा की थी लेकिन इस विचार का समयाभाव के कारण मौका नहीं मिला। आप जानते हैं कि हमारे बिहार के अन्दर एक करोड़ लोग अकाल से पीड़ित हैं। सहरसा जिले, दरभंगा जिले में बुरी हालत हो रही है और अकाल की स्थिति पैदा हो रही है। इसी तरह से राजस्थान में अकाल की नौबत है। इसलिए अकाल की स्थिती के बारे में इसी सैशन में विचार के लिए समय निकालना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि हमारे देश के इंजिनियर्स बेकारी से तंग आकर तमाम जगह आन्दोलन कर रहे हैं। पटना में उनका सत्याग्रह आन्दोलन

चल रहा है। उनपर लाठियां बरसाई गईं। इसलिए यह बहुत आवश्यक है कि यहां इस सिलसिले में इसी सैशन में बहस हो कि इन बेकार इंजीनियरों को हम कैसे काम देंगे ? इस बात पर भी मैं आपका ध्यान खींचना चाहता हूं ताकि इस पर भी इसी सत्र में बहस के लिए समय मिल जाय।

SHRI S. K. TAPURIAH (Pali) : There are more important subjects pending before Parliament concerning a larger number of people, than a few princes, like discussion on the Fourth Plan. Also what is the fate of the Resolution given notice of under rule 193 for a discussion on the growing Naxalite activities all over the country, specially Bengal and the paralysis of the administration in that State where the Government is not even on talking terms with the Chief Adviser and where he is rebuking senior advisers in public, resulting in complete demoralisation in Writers Building with no papers moving and no administrator listening to him.

SHRI SHRI CHAND GOYAL (Chandigarh) : It is practically over two months that we are having the budget session. In the beginning, it was decided that all motions, either no-day-yet named or others under rule 193, would be taken up as soon as the financial business was over. Now that it will be over by about the 6th, it is absolutely necessary that some of these motions must be taken up.

Then there are important reports, like the report of the Public Service Commission, report dealing with the industrial policy of Government and so on. These have not been discussed for a considerable time for lack of time. These should also figure in the agenda so that we can take them up.

SHRIMATI SUCHETA KRIPALANI (Gonda) : I would emphasise that we would very much like a discussion on Naxalite activities all over the country. Also when are Government proposing to bring the Bills for the abolition of the Upper Houses in Bihar and U. P.?

SHRI R. K. AMIN (Dhandhuka) : The Report of the Licensing Policy Inquiry Committee—Dutt Committee Report—has been published, but Parliament has not had an opportunity to discuss it. Without taking Parliament into confidence, the policy is being pursued by the Government. It is high time that the Report is discussed, the views of Parliament obtained and then the policy implemented.

13 hrs.

SHRI M. L. SONDHI (New Delhi) : It has been the practice in connection with the foreign policy of this country to welcome any initiative by Asian countries. On the question of Combodia, this Government is not availing itself of the helpful advice of our Asian neighbours but is subjecting itself to great power pressure. Combodia is bleeding to death. The Prime Minister is sitting pretty here without lifting a little finger to welcome the initiative that Mr. Adam Malik has taken. Praliament should be taken into confidence. They are departing from the established policy, which Parliament has approved of, always backing Asian initiative. This Government must be charged with betrayal of this policy.

श्री नवल किशोर शर्मा (दौसा) : मैं श्री शास्त्री की मांग का समर्थन करता हूं कि अकाल के बारे में इस सदन में विचार होना चाहिये। खास तौर से राजस्थान में बराबर पिछले पांच साल से ऐसी स्थिति चली आ रही है। राजस्थान भयंकर अकाल के दौर से गुजर रहा है इस लिये अकाल के बारेमें सदन में चर्चा होनी चाहिये और उस पर विचार होना चाहिये।

SHRI RAGHU RAMAIAH : With regard to the Privy Purses Bill, as Shri Banerjee has said, the Home Minister has already made a statement. I have nothing to add to it. The statement is *pucca*. hon. Members wanted discussion of various important matters. Actually, the business provided here for next week excludes the time given to the Finance Bill. We will take about seven hours for the Finance Bill. Therefore, discussion of my other matter can only be considered in the week thereafter. There are so many important matters, as hon. Members pointed out there is

[Shri Raghu Ramaiah]

the Report of the Scheduled Castes and Scheduled Tribes, the Draft Fourth Plan, discussion on industrial policy and so on. All this will be considered according to the time available.

श्री रामसेवक यादव : गन्ने की जो हालत है वह बहुत महत्वपूर्ण सवाल है उस पर जरूर विचार होना चाहिये ।

MR.SPEAKER : I will get them discused in the Business Advisory Committee, and we will find out time.

श्री शिव नारायण (बस्ती):यह बहुत इम्पार्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है । यू . पी. और बिहार में रेजोल्यूशन पास हो गया हैं कौंसिल के अबालिशन का । उसके बारे में कोई जिक्र नहीं किया गया । प्राइम मिनिस्टर की ड्यूटी हैं कि वह इस का जवाब दें ।

MR. SPEAKER : In future when such reports are presented, it is much better that Members give their views to their party leaders who can speak, so that no regular debate is allowed.

THE MINISTER OF LAW (SHRI GOVINDA MENON) : With reference to the Upper House in Bihar, one or two days back a communication was received from the Government of Bihar, and the matter is being processed. So far as U. P. is concerned, we have read it only in the newspapers.

13.05 hrs.

The Lok Sabha adjourned for Lunch till Fourteen of the Clock.

The Lok Sabha re-assembled after Lunch at four minutes past Fourteen of the Clock

[MR. DEPUTY-SPEAKER *in the Chair.*]

MATTER UNDER RULE 377

FINANCE BILL, 1970

MR. DEPUTY-SPEAKER : Before we take up the next item on the agenda, namely, the Finance Bill, I have to inform the House that I have received a letter from Mr. Dandeker who wants to raise certain points under rule 377 relating to this Bill. Mr. Dandeker.

SHRI N. DANDEKER (Jamnagar) : I am raising this point under rule 377 rather than as a point of order, though I am told that it could be done either way. I do not raise a point of order because I hate to interrupt any Minister when he speaks. Rule 377 is a simple rule where by :

> "A member who wishes to bring to the notice of the House any matter which is not a point of order shall give notice to the Secretary in writing stating briefly the point which he wishes to raise in the House together with reasons for wishing to raise it, and he shall be perimtted to raise it only after the Speaker has given his consent and at such time and date as the Speaker may fix".

You, Sir, have been kind enough to allow me to make my points, and I will try to be as brief as possible. The substance of the point that I am making—I may as well put the cart before the horse is this: that this is a money Bill, and that a money Bill,-I will presently read the reference in the Constitution to money Bills,-must be strictly confined to matters relating to money, raising of money, and taxes and so on plus only such matters as may be strictly consequential thereto. Sir, my submission is that this Finance Bill proposes a whole range of substantive amendments to the Income-tax Act, Wealth-tax Act, Gift-tax Act and the Companies' Profit Surtax Act, all of which ought not to be here but ought to be the subject matter of a separate Bill. I will presently elaborate on that point further.

Now, I would like to take up this matter logically from where it begins, namely, article 110 (1) of the Constitution of India which defines Money Bills thus: